साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 43 | प्रति सोमवार इंदौर, 27 मई से 2 जून 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

इरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के काफिले का हेलिकॉप्टर क्रैश हादसा या साजिश..?

ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के काफिले के एक हेलीकॉप्टर की क्रैश होने की खबर है. कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री सवार थे. अभी तक दोनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है. इस बीच क्रैश साइट पर रेस्क्यू टीम के पहुंचने की पहली तस्वीर सामने आई है. हेलीकॉप्टर की क्रैश हादसा या साजिश?

ईरानी मीडिया के मुताबिक, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के काफिले में से दो हेलीकॉप्टर सुरक्षित अपनी जगह पहुंच चुकी है. जबकि हेलीकॉप्टर की अजरबैजान देश की सीमा पर स्थित जोल्फा के जंगल में हार्ड लैंडिंग हुई. ईरान के गृहमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति से संपर्क नहीं हो पा रहा है. जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां घना कोहरा छाया हुआ है. इसको लेकर रेस्क्यू टीम को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि एक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है. टीम से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. वहीं, ईरानी सुरक्षा सूत्रों का दावा- हत्या के प्रयास की संभावना से इनकार नहीं, 3 में से 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित लैंड तो रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्यों हुआ क्रैश? ईरान के अधिकारियों के मुताबिक क्रैश साइट पर बारिश की बजह से विजिबिलिटी में कुछ सुधार आया है. जिससे रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट पहुंचने में आसानी होगी.

इब्राहीम रायसी की मौत दुर्घटना या साजिश

ईरान हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण कौन था: ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी अपने विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ अजरबैजान में एक बांध उद्घाटन

समारोह से लौट रहे थे, जब उनके हेलीकॉप्टर की जोल्फा शहर में 'हार्ड लैंडिंग' हुई। लगभग सोलह घंटे के खोज अभियान के बाद, यह पुष्टि की गई कि ईरान राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 'कोई जीवित नहीं बचा' था और ईरानी राष्ट्रपति का निधन हो गया था। घटनाओं के इस चौंकाने वाले मोड़ का ईरान के राजनीतिक परिदृश्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और इसका असर अन्य देशों के साथ साझा संबंधों पर भी पड़ेगा। जबकि ईरान के उपराष्ट्रपति मुहम्मद मुखबर वर्तमान में ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, हर किसी के मन में एक सवाल है कि ईरान हेलीकॉप्टर दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार था, इब्राहिम रायसी की मौत एक दुर्घटना थी या एक साजिश। यहां नवीनतम रिपोर्ट और विशेषज्ञों का इस बारे में क्या कहना है... ईरानी मीडिया के आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की मौत किसी साजिश का हिस्सा नहीं है और यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। राज्य समाचार मीडिया ने बताया है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना 'तकनीकी विफलता' के कारण हुई, जो घने कोहरे और खराब मौसम के कारण हुई थी; इसमें कोई साजिश या तीसरा पहलू शामिल नहीं है.

शान्त सरीन कहते हैं जबकि मीडिया ने पहले ही इस संबंध में एक बयान जारी कर दिया है, विदेश मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने कहा कि यह घटना हर किसी के लिए आश्चर्य और सदमे की तरह थी, उन्होंने कहा कि अभी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हेलीकॉप्टर की ऐसी मुलाकात क्यों हुई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की घातक हेलिकॉप्टर दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

एएनआई ने सरीन के हवाले से कहा, 'और निश्चित रूप से, जैसा कि हर कोई अनुमान लगा रहा है क्या यह किसी प्रकार की तोड़फोड़ थी? **(शेष पेज 6 पर)**

देश में सभी अविश्वसनीय, जनता किस पर करें भरोसा

ईडी सीबीआई लोकायुक्त सभी जांच एजेंसियां बिकाऊ चाहिए खरीददार

सभी में मनुष्य, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, भय के पुतले। जीवन है तो सामांजस्य से चलना ही होगा

धरती पर मनुष्य शैतान प्राणी माना जाता व होता है। समाज को चलाने के लिए नियम कानून और मापदंड बनाए जाते हैं। बनाए ही इसलिये जाते हैं। ताकि समाज को विश्वास के साथचलाया जा सके परंतु नियम मनुष्य बनाता है और स्वयं ही तोड़ता है।

समाज व समाज के बाद राष्ट्र को चलाने के लिए नियम कानूनों मान दंडों को बनाने स्थापित करने का मूल आधार होता है, कि सभी को न्याय समानता और जीवन का शांति से जीने का अधिकार मिले। और इस इन सबको चलाने के लिए न्यायालयों की स्थापना की जाती है ताकि वे समाज व राष्ट्र की व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए अन्याय को रोकें और अन्याय करने वालों को निर्धारित मांडना के अनुकूल सजा देकर भविष्य में होने वाले अपराधों को हतोत्साहित कर सकें। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोकतंत्र को चलाने के लिए जो चुनाव की व्यवस्थाएं जो होती है उन्हें अपराधिक प्रवृत्ति के नेता अधिकारी छल, बल, दल से अपहरित कर सत्ता हथिया लेते हैं। सिर्फ सत्ता को अपने बाप की जागीर समझ, मनमानी तरीके से दोहन करते हैं जैसा कि अभी वर्तमान में भारत में व इसके सभी राज्यों में चल रहा है। ईडी सीबीआई लोकायुक्त एटीएस एसटीएफ ईओडब्ल्यु आदि सभी जांच एजेंसियों में सब घोर चुने हुए जालसाज डकैत लुटेरे भारी भ्रष्ट होते हैं। जो पुलिस विभाग की नौकरी में जब ज्यादा बदनाम, चारों तरफ उनके कुकर्मों, भ्रष्टाचार लूट डकैती वसूली अपराधियों को पालने, संरक्षण देने महीना वसूली के कारण विभाग बदनाम होने लगता है। बहुत सारी जांचें उनके ऊपर लंबित हो जाती हैं। **(शेष पेज 6 पर)**

पीएम मोदी का बिल बकाया!

एक साल पहले पीएम मोदी ने किया था मैसूर का दौरा, होटल ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल मैसूर के दौर पर गए थे। उस दौरान पीएम मोदी जिस होटल में रुके थे उसने बिल का भुगतान ना होने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है।

दरअसल, अप्रैल 2023 में अपनी मैसूर यात्रा के दौरान जिस होटल में रुके थे, उसका करीब 80 लाख रुपए का बिल बकाया है। होटल ने बिल का भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। मोदी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के 50 साल पूरे होने का उद्घाटन करने के लिए मैसूर में थे। इसी दौरान वो इस होटल, रेडिसन ब्लू प्लाजा में रुके थे।

होटल प्रबंधन ने कानूनी कार्रवाई की धमकी

1 जून 2024 तक बकाया बिल का भुगतान ना होने की स्थिति में होटल प्रबंधन ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। डॉ. बसवराजू ने कहा कि राज्य सरकार ने इस आधार पर राशि की प्रतिपूर्ति करने के केंद्र के निर्देशों को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि यह केंद्र सरकार का कार्यक्रम था।

सहायता का आश्वासन दिया

रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य वन विभाग को 3 करोड़ की लागत से 9 से 11 अप्रैल तक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। वन विभाग को 100 केंद्रीय सहायता का आश्वासन भी दिया गया था। यह कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और एनटीसीए के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अल्प सूचना पर आयोजित किया गया और आयोजन की कुल लागत 6.33 करोड़ हो गई थी। हालांकि, केंद्र द्वारा 3 करोड़ की राशि जारी की गई थी। राज्य वन विभाग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के बीच संचार के आदान-प्रदान के बावजूद करीब 3.33 करोड़ की शेष राशि अभी तक जारी नहीं की गई है।

राज्य ने भुगतान करने को कहा

कर्नाटक के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने 29 सितंबर, 2023 को उप महानिरीक्षक, एनटीसीए, नई दिल्ली को पत्र लिखकर बकाया राशि की याद दिलाई, लेकिन एनटीसीए ने 12 फरवरी, 2024 को लिखा कि **(शेष पेज 6 पर)**

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

मोदी का जादू फेल, लक्ष्य भी ध्वस्त

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जिस कथित करिश्माई व्यक्तित्व के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में अपने बल पर 370 और नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) के बल पर 400 सीटों से ज़्यादा का लक्ष्य निर्धारित किया था, वह मतदान के पांच चरण निकलते-निकलते इसलिये हवा में उड़ता नजर आ रहा है क्योंकि अब न तो मोदीजी के पास कोई नयी बात कहने को रह गई है और न ही उनके व्यक्तित्व से लोग आकर्षित हो पा रहे हैं। इसका कारण यही है कि भाजपा के विमर्श का आधार उनका चेहरा था, जबकि उन्हें टक्कर देता इंडिया गठबन्धन विमर्श के आधार पर कई करिश्माई व्यक्तित्व गढ़ चुका है जो देश के चारों दिशाओं में धूम मचा रहे हैं।

विमर्श की बात करें तो लगता है कि भाजपा के पास अपना कोई भी नैरेटिव नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वही भाजपा का विमर्श और विषय होता है; और मोदी जी जो कहते हैं वह कांग्रेस या इंडिया गठबन्धन के नेताओं द्वारा कही गई किसी बात की प्रतिक्रिया मात्र होती है। अब भाजपा की सभाओं में दिखने वाली भीड़ केवल जुटाई गई होती है जो लौटते वक़्त कोई नयी बात लेकर नहीं जा रही है। चूंकि यह हुजूम लाया हुआ है इसलिये वह मोदी या भाजपा के भाषणों के दौरान कहां पर 'मोदी मोदी' कहना है, बखूबी जानता है। इसे ही दरबारी मीडिया प्रस्तुत करता है। यह माहौल बनाने में उसका योगदान होता है जबकि अब तक सम्पन्न हुए 418 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद जो अनुमान आ रहे हैं वे साफ बता रहे हैं कि भाजपा-एनडीए लगभग सभी राज्यों में पिछड़ रही है। मोदी मैजिक तो हवा में उड़ ही चुका है, वह अपने साथ 370-400 पार के नारे को भी उड़ा ले गया है।

अनेक ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि खुद भाजपा कार्यकर्ता एवं उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इस बार के चुनाव को लेकर उदासीन हैं। इसका एक संकेत सभी चरणों में कम मतदान का होना है। भाजपा व संघ दोनों के ही कार्यकर्ता जानते हैं कि मोदी अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने

के लिये संघर्षरत हैं और वे 400 पार लाकर वह करना चाहते हैं जो भाजपा के कहीं पहले संघ का लक्ष्य रहा है- संविधान व लोकतंत्र को समाप्त कर मनुवादी व्यवस्था को लाना। ऐसे आड़े वक्तू में अगर दोनों संगठनों के कार्यकर्ता मतदान कराने के लिये 2014 एवं 2019 की तरह घरों से नहीं निकल रहे हैं तो मानकर चलना होगा कि इन पर से मोदी की पकड़ छूट चुकी है। इन संगठनों के कार्यकर्ता यह भी जान गये हैं कि जिन उद्देश्यों के लिये नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया है वह हासिल करने के लायक नहीं है। सम्भवतः उन्होंने यह भी सोच लिया है कि अगर हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा को साकार करना भी है तो वह कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में तो बिलकुल नहीं करना है क्योंकि दोनों ने इसके प्रति लोगों में शंकाएं एवं अरुचि पैदा कर दी है।

इन दोनों संगठनों के कार्यकर्ता यदि अपनी नाराजगी या उदासीनता जो भी रही हो, उसे त्यागकर मोदी की मदद के लिये आना भी चाहते तो अब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान के बाद तो बिलकुल ही आने से रहे जिसमें नड्डा ने कहा है कि 'अब भाजपा बड़ी हो चुकी है तथा उसे अब राजनैतिक कामों के लिये संघ की ज़रूरत नहीं रह गई है।' नड्डा का यह भी मानना है कि 'पहले चाहे संघ पर भाजपा आश्रित थी पर अब दोनों अपने-अपने कामों को स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं- भाजपा राजनीतिक काम और संघ विचारधारा सम्बन्धी कार्यकलाप व सांस्कृतिक गतिविधियां।' यह तय है कि इस बयान के बाद अब भाजपा को अगले तथा अंतिम दो चरणों में संघ की मदद मिलने से रही। 400 सीटों का लक्ष्य पाना तो दूर, अब वह सत्ता बचा ले यही बहुत है।

कुछ बातें और जो सामने आई हैं उनमें प्रमुख यह है कि भाजपा ने जिस विषय को इस चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाने की सोची थी, वह पूरी तरह से गौण हो गया है- अयोध्या में राम मंदिर का। 2019 के बाद से ही बड़े सुनियोजित तरीके से मोदी ने रामलला मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कराया और आनन-फानन में उसका निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, आधे-अधूरे रूप से निर्मित मंदिर की प्राणप्रतिष्ठा स्वयं मोदी ने एक भव्य समारोह में की। कुछ दिनों पहले एक प्रतिष्ठित संगठन ने जो सर्वे किया उसके नतीजों ने भाजपा को मैदान से ही बाहर कर दिया। सर्वेक्षण ने बतलाया कि केवल 6 फ़ीसदी लोग ही राम मंदिर को चुनाव के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं। ज्यादातर लोगों ने बेरोज़गारी व महंगाई को सबसे अहम मसले बतलाकर मोदी व भाजपा की सारी तैयारियां ध्वस्त कर दीं। यही कारण है कि खुद मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में इस विषय का सबसे कम बार उल्लेख किया। कांग्रेस के कथित परिवारवाद सम्बन्धी मोदी-शाह के बयानों से लोग ऊब चुके हैं और विपक्षी नेताओं पर लगाये जाने वाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों पर भी कोई भरोसा नहीं कर रहा क्योंकि सभी भ्रष्टाचारियों के लिये भाजपा ने द्वार खोल रखे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पर्दाफाश है ही।

जिस एनडीए के दम पर भाजपा 400 पार जाना चाहती है उसकी सभाओं में सहयोगी नेताओं की मौजूदगी नहीं होती और इंडिया की तरह उसकी संयुक्त सभाएं भी नहीं होतीं। मोदी मैजिक फेल, लक्ष्य भी ध्वस्त...!

है पुरूष तेरी कहानी

कौन है पुरुष?
भगवान की ऐसी रचना
जो बचपन से ही त्याग
और समझौता करना सीखता है।
वह अपने चॉकलेटस का
त्याग करता है
अपनी बहन के लिये।
वह अपने सपनो का
त्याग कर माता-पिता की
खुशी के लिये उनके अनुसार
कैरियर चुनता है।
वह पूरी पॉकेट मनी अपनी
गर्ल फ्रेंड के लिये
गिफ़्ट खरीदने में लगाता है।
वह अपनी पूरी जवानी
बीवी-बच्चों के लिये
कमाने में लगाता है।
वह सबका भविष्य बनाने के लिये
लोन लेता है और बाकी की ज़िंदगी
उस लोन को चुकाने में
लगाता है।
इन सबके बावजुद वह
पूरी ज़िंदगी पत्नी माँ और बॉस से
डांट सुनने में लगाता है।

पूरी ज़िंदगी पत्नी, माँ, बॉस
और सास उस पर
कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
उसकी पूरी ज़िंदगी
दूसरो के लिये ही बीतती है
समाज के दोहरे तानों से तो
सभी परिचित ही होंगे जैसे :
बीवी पर हाथ उठाये तो बेशर्म
बीवी से मार खाये तो बुजदिल
बीवी को किसी और के साथ देख कर
कुछ कहे तो शक्की
चुप रहे तो डरपोक
घर से बाहर रहे तो आवारा
घर में रहे तो नाकारा
बच्चों को डांटे तो ज़ालिम
ना डांटे तो लापरवाह
बीवी को नौकरी करने से रोके तो पशोजिव
बीवी को नौकरी करने दे तो बीवी की
कमाई खाने वाला
माँ की माने तो चमचा
बीवी की माने तो जोरु का गुलाम
पूरी ज़िंदगी समझौता, त्याग और
संघर्ष में बिताने के बावजुद वह
अपने लिये कुछ नहीं चाहता।

सत्ताधीशों की कठपुतली जालसाज चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को दिया गलत शपथ पत्र

चुनाव आयोग ने फिर सर्वोच्च न्यायालय में तत्काल मतगणना का प्रतिशत दिखाने के लिए लगी याचिकाओं पर उसकी सुनवाई के समय ग़लत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है. चुनाव आयोग ने कहा है कि फार्म 17C सीलबंद लिफाफे में स्ट्रांग रूम में जमा हो जाता है. इस स्थिति में उसे सार्वजनिक करना संभव नहीं है. जो सरासर साफ पूरा झूठ है। जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को चाहिएकि वह चुनाव आयोग कोतत्काल निलंबित करने का आदेश दे।

यह अर्धसत्य है. 33 साल तक मैं चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूं और मैंने अब तक देखा है कि फार्म 17C की एक प्रति सीलबंद लिफाफे में स्ट्रांग रूम में वोटिंग मशीन के साथ जमा की जाती है और दूसरी प्रति खुले लिफाफे में अलग से अन्य कागजातों के साथ दी जाती है। इसी प्रति के आधार पर ही मतदान प्रतिशत का हिसाब लगाया जाता है.

लोकसभा चुनाव में ईवीएम एवं फार्म 17C विधानसभा क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग काउंटर पर जमा किया जाता है और हर विधानसभा सिगमेंट का प्रधान ARO (सहायक निर्वाचन अधिकारी) होता है. यह अधिकारी उस विधानसभा क्षेत्र में हुए कुल मतदान का प्रतिशत, मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले स्त्री-पुरुष की संख्या का आकलन कर जिला निर्वाचन अधिकारी को देता है. जिला निर्वाचन अधिकारी इसे राज्य निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से निर्वाचन आयोग को भेजता है.

यदि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हो एवं उसकी नियत सही हो तो चुनाव के उपरांत उसी दिन फार्म 17 C

को चुनाव आयोग के वेबसाइट पर डाला जा सकता है. इसके लिए सभी ARO को अधिकृत किया जाना चाहिए. सभी ARO चुनाव समाप्ति के बाद उसी दिन अपने अपने विधानसभा सिगमेंट का फार्म 17 C स्कैन कर वेबसाइट पर डाल देंगे. देश भर के डाटा को एक जगह एकत्रित कर फिर वेबसाइट पर डालने की कवायत नहीं करनी पड़ेगी और आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल नहीं उठेगा.

लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब आयोग के निष्पक्ष होने की संभावना एवं नियत बची हो.

जल संसाधन संभाग देवास में चल रहा भ्रष्टाचार का तांडव

चंद्रकेसर नहरों की लाइनिंग का पैसा हजम दतूनी नहर भी फूटी

कर्यपालन यंत्री जादौन 1-1, 2-2 सप्ताह गायब, इसीलिए सूचना के अधिकार में अपील पर निःशुल्क देने के आदेश के बाद भी हरामखोरों ने 10 महीने के बाद भी जानकारी नहीं दी।

मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग का देवास संभाग जिसका कार्यपालन यंत्री घोर भ्रष्ट जालसाज हरामखोर जादौन ने मोटा पैसा खर्च कर संभाग में पदस्थी ली, और किराए के वाहनों में एक को छोड़कर सभी निजी लोगों से बिना टैक्सी परमिट केचलाई जा रही है इसमें खुद का भी एक बहन टैक्सी परमिट में पूर्ण होने के बावजूद भी 26000 से ज्यादा का मासिक किराया उठाने पेट्रोल डीजल शासन की तरफ से भरवाने का खेल तो किया ही जा रहा है साथ ही शासन के राजस्व को जो हर 3 महीने में रु. 3000 जमा करने पड़ते हैं टैक्सी परमिट के उसका भी भुगतान किसी भी वहां का नहीं किया जा रहा है इसके संबंध में परिवहन अधिकारी को संज्ञान लेकर वाहनों को व्यक्त करने के साथ इस पर जांच बैठाई जानी चाहिए। इन सब भ्रष्टाचारों को जालसाजियों को रोकने, नियंत्रित करने केंद्र सरकार का जो संभागीय लेखाकार आदित्य डेबिड बैठाया हुआ है। वह हरामखोर क्योंकि वह अनुसूचित जनजाति जाति में पैदा हुआ जरूर होगा परंतु जब वह ईसाई बन गया धर्म परिवर्तन करने के बाद में उसे किसी भी प्रकार के जातिय आरक्षण मिलने की पात्रता नहीं थी। इसके विपरीत उसने अनुसूचित जाति जनजाति के आधार पर नौकरी प्राप्त की जो फर्जी जालसाजी पूर्ण है जिसकी जांच की जाकर उसको हटाया जाना चाहिए।

सूचना के अधिकार में आवेदन लगाने और न मिलने पर अपील लगाने पर अधीक्षण यंत्री द्वारा स्पष्ट आदेश देने के बाद में किन्हे निशुल्क जानकारी प्रदान की जाए इस जालसाज ने जानकारी देने की अपेक्षा उल्टी सीधी दिल्ली स्कूल प्रकाशित किया गया था। यही हरामखोर सभी प्रकार के फर्जी बिलों को पास करने में आपको बताया था पाठ से 30% तक कमीशन खा जाता है। वही हाई टैक्सियों के बिल में भी किया जा रहा है की जो टैक्सी परमिट की गाड़ियां शासकीय विभागों में लगाई जाती है उन्हें हर 3 महीने में रु.3000 जमा करने होते हैं परिवहन कार्यालय में परंतु सभी गाड़ियां निजीस्तर की है तो यह कार्यपालन यंत्री के साथ मिलकर सर फर्जी वाला कर रहा है और पांच गाड़ियों के साथ से पिछले 3 सालों में परिवहन की लाखों रुपए की टैक्सी कोटे का शुल्क नहीं चुका रहा है बेशक यह कहानी पूरे मध्य प्रदेश के सभी विभागों में जिनमें इस प्रकार के टैक्सी कोटे के वाहन संलग्न किए जाते हैं। इस प्रकार की लगभग पूरे प्रदेश में 50000 से ज्यादा वाहन टैक्सी कोटे का शुल्क नहीं चुका रहे। हाल ही में यहां पर दौनी चंद्र केसर व अन्य बांधों की नहरों के साफ सफाई और मरम्मत का जो रुपए 15 करोड़ से ज्यादा विभिन्न मदों में आया है। वह भी फर्जी कामों के माध्यम से हजम करने का षड्यंत्र न केवल जादौन आदित्य डेविड एसडीओ गुंजन सक्सेना, अजनार, यादव, चा आदि के साथ उपयंत्री आदि भी मिलकर किस्से बनते में लगे हुए हैं बेशक इतने सारे भ्रष्टाचारों जालसाजियों की शिकायतों के बाद भी, जबकि जादौन का हाल तो यह है, कि वह बिना बताए बिना छुट्टी के सप्ताह दो सप्ताह तक गायब रहता है। और यह हाल उसका पिछले 2 साल से सतत चल रहा है। करोड़ों रुपए की चंद केसर बांध की तीनों नहरों दाएं बाएं और जीएमटी में लाइनिंग का पूरा कार्य हो चुका है, जबकी सतवास बिजवाड़ मार्ग परसड़क मार्ग पर जब मैने देखा तो तीनों में कोई कांक्रीट नहीं हुआ था जिसके फोटो यहां लगाए जा रहे हैं।

18 करोड़ की लागत से बनी नहर चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट

निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही नहर जगह-जगह से क्षतिग्रस्त, पड़ीं दरारें

देवास। प्रदेश व केंद्र सरकार किसानों की जमीन को सिंचित करने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये खर्च कर नहर का निर्माण करती है, किंतु निर्माण एजेंसी व ठेकेदार मिलकर इन योजनाओं पर पतीला लगा देते है। देवास जिले के कांटाफोड़ से सतवास तक 18 करोड़ की लागत से बनने वाली 41 किलोमीटर लंबी नहर भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही क्षतिग्रस्त होकर इस नहर में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई है। बावजूद इसके जल संसाधन विभाग के अधिकारी उचित कार्यवाही करने के बजाय ठेकेदार की पैरवी करते नजर आ रहे है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर की शिवमुरम कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वर्ष 2022 में कांटाफोड़ स्थित चंद्रकेशर बांध से लेकर सतवास तक नहर बनाने का ठेका लिया। 18 करोड़ की लागत से बनने वाली इस नहर की लंबाई लगभग 41 किलोमीटर है और ठेकेदार को जल संसाधन विभाग ने निर्माण-कार्य पूर्ण करने के लिए 18 माह की अवधि दी थी, जो पूर्ण हो चुकी है और नहर अभी लोहारदा मंडी तक ही पहुंची है, अर्थात 60 फीसदी से अधिक काम ही हुआ है। उधर इस नहर का क्षतिग्रस्त होना भी शुरु हो गया है। दरअसल सरकार की मंशा है कि इस नहर के माध्यम से सैकड़ों किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाए, ताकि उनकी फसल सिंचित हो गए, किंतु दुर्भाग्य है कि सरकारी तंत्र व ठेकेदार की मिलीभगत से नहर का काम पूर्ण होने से पहले ही नहर जगह-जगह से क्षतिग्रस्त होने लगी है और दरारें पड़ रही है। बावजूद इसके संबंधित अधिकारी अनदेखी कर रहे है। यहां तक कि ठेकेदार का सीधे-सीधे बचाव भी करने में लगे है। इससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों की भी मिलीभगत है।

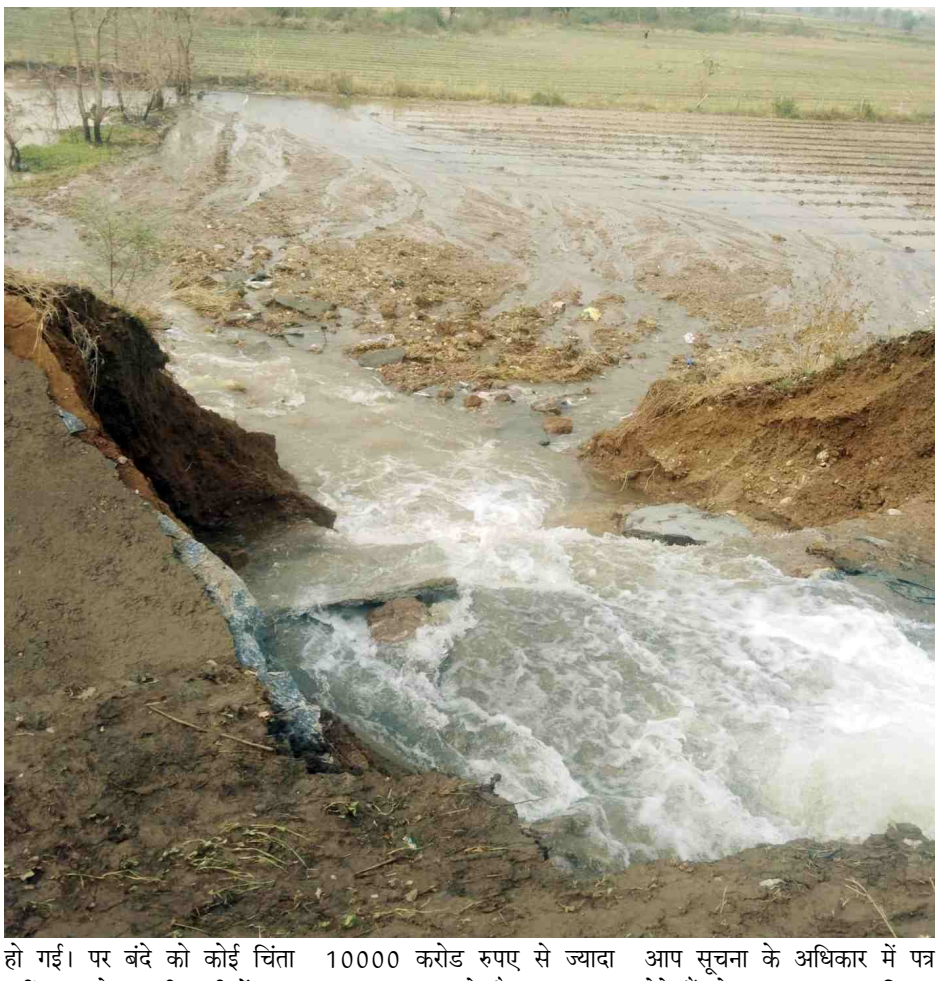

ठेकेदार का बचाव करते नजर आए विभागीय अधिकारी

जब इस संबंध में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री लकपतसिंह जादौन से चर्चा की गई तो वे ठेकेदार का बचाव करते हुए नजर आए और उन्होंने बताया कि अभी निर्माण कार्य जारी है। ठेकेदार को 5 साल तक मेंटेनेंस भी करना है। यदि कहीं टूट-फूट हुई है, तो ठेकेदार द्वारा मरम्मत की जाएगी। उन्होंने ...

अप्रैल के महीने में किसानों को पानी देते समय दतूनी नहर इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ था। फूट गई थी किसानों के खेतों में पानी भर जाने कारण उनकी फसलें बर्बाद

हो गई। पर बंदे को कोई चिंता नहीं हरामखोर अपनी मस्ती में मस्त यहां वहां घूमता रहता है जबकि उसके ऊपर से कलेक्टर प्रधान सचिव आदि ने जांच के आदेश दिए इसके अभी तक जांच भी नहीं हुई और मरम्मतकारी भी नहीं किया गया और बरसात सर पर आ गई है स्वाभाविक है। बरसात आना भी लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, नगर निगमों पालिकाओं, नर्मदा घाटीवी अनिक अनेकों कार्य विभागों के लिए भ्रष्टाचार की लाटरी लग जाने के समान होता है। आदित्य कार्य जनवरी-फरवरी से लेकर मार्च तक स्वीकृत होते हैं और पूरा करते-करते जून जुलाई हो आ जाता है कार्य नहीं किए जाते हैं कागजों पर दिखाकर फर्जी बिल लगाकर पैसा हजम कर लिया जाता है। यदि पूछताछ और जांच हो गईतो कह दिया जाता है साहब हमने को काम करवाया था बरसात में खराब हो गया। इस प्रकार सभी कार्य विभागों में हर साल बरसात के नाम पर 10000 करोड रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार करके पैसा हजम कर लिया जाता है।

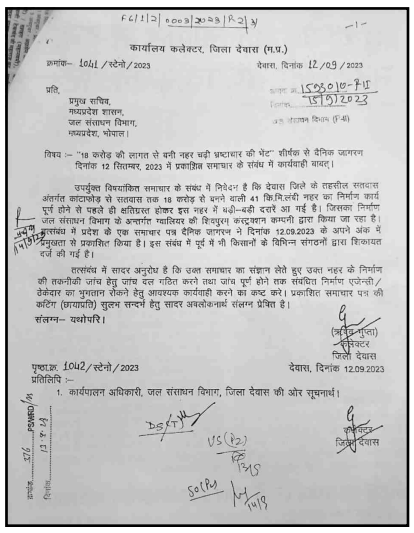

वैसे ही जल संसाधन विभाग में भी बांधों नहरो की साफ सफाई मरम्मत के लिए गए कार्यों को कागजों पर करवा पैसा हजम कर जाने और हल्ला मछली पर बरसात हो जाने परयहां भी यही कह दिया जाता है की बरसात हो जाने के कारण हो सकता है कुछ खराब हो गया हो और प्रकार देवास संभाग में भी हर साल पुराने तालाब बांधों नहरों पर भी देवास उज्जैन इंदौर रतलाम धार शाजापुर रतलाम अलीराजपुर झाबुआ खंडवा खरगोन बड़वानी बुरहानपुर आगर मालवा मंदसौर नीमच जो पुर्व में इंदौर नर्मदा ताप्ती कछार में आते थे। हर साल लगभग 2000 करोड रुपए यहां बैठे भ्रष्ट कार्यपालन यंत्रियों सहायक यंत्रियों द्वारा पीने और यहां बैठे अधीक्षक यांत्रियों मुख्य अभियंता से लेकर उसका हिस्सा प्रमुख अभियंता प्रधान सचिव और मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है। बेशक स्टाफ की चारों तरफ भारी कमी है। 90% स्टाफ यंत्री और अभियंता प्रभार दो प्रभार लो पर चलने के कारण, सब अपने प्रभार वसूली में लगे रहते हैं इसलिए कोई भी कार्य नियम कायदे कानून से नहीं हो रहा। फिर देवास में जो 6000 करोड़ की हॉट पिपलिया उद्वहन सूक्ष्म सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है जहां पर एलएनटी सेकडों करोड़ का सर्वे के नाम पर ही भुगतान ले चुका है यही कारण है कि यह हरामखोर सूचना के अधिकार में कोई भी जानकारी देना पसंद नहीं करते और दूसरी तरफ आप सूचना के अधिकार में पत्र देते हैं तो यह रु. 5 का टिकट लगा लिफाफा फॉर गर्लफ्रेंड देते हैं और जानकारी को नोटिस बोर्ड के दाएं बाएं लटका देता है परंतु यह निकम्मा ब्रेस्टन की फौज आवेदक को निम्नानुसार पंजीकृत डाक से जानकारी इसलिए नहीं भेजती ताकि यह सूकरों की आसानी से अपने भ्रष्टाचार को छुपाते हुए आवेदक को जानकारी देने से बच जाएं। और जनधन को अपने आप की जागीर समझ हजम करते रहें कोई उनसे कुछ ना बोले यह फर्जी 30 कूलरों के दिल लगाकर स्टेशनरी की खरीदी दिखाकर फर्जी फोटोकॉपी दिखाकर उसके बिल हजम करते रहें।

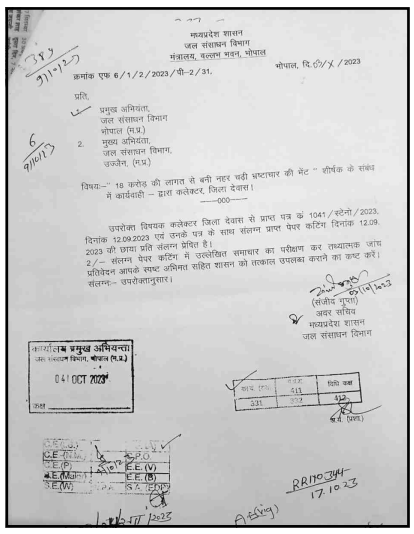

टैक्सी कोटा परमिट व संलग्न वाहनों के लाग बुक की, पेट्रोल डीजल के पीओल के बिलों की कॉपी न्यू दिन माप पुस्तिका में जो फर्जी नाप चढ़ाए जाते हैं उसकी जानकारी मांगने पर उसको हजम कर जाएं हर बिल के भुगतान में कार्यपालन यंत्री को 10% काम की जांच स्वयं साइट पर जाकर करनी चाहिए और भरी हुई एमबी को बिल भुगतान के पूर्व ही जांचना चाहिए। नहीं पाए जाने पर ही उसका भुगतान किया जाना चाहिए परंतु यह डफर जादौन जो मूलत उप यंत्री है। मोटा पैसा खर्च कर एसडीओ बना और प्रभारी देवास संभाग का कार्यपालन यंत्री बनकर बैठा हुआ है। आखिर प्रदेश सरकार काजल संसाधन विभाग ऐसे निकंम्मे भ्रष्टों को हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट बिना अनुभव ज्ञान के कैसे सौंप कर जनधन की बर्बादी केवल अपनी लूट के लिए करवा रहा है।

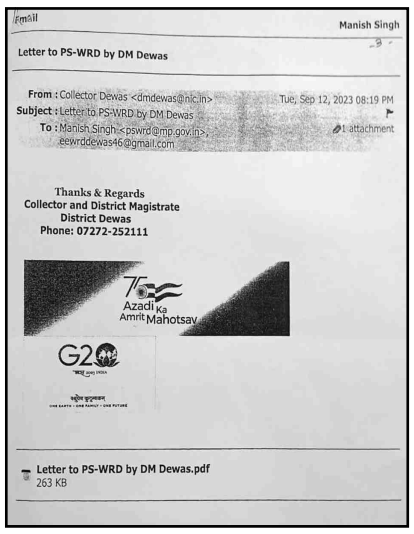

कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

Letter to PS-WRD by DM Dewas

Thanks & Regards
Collector and District Magistrate
District Dewas
Phone: 07272-252111

Letter to PS-WRD by DM Dewas.pdf

साप्ताहिक समय माया

इन उपायों से भी पा सकते हैं जोड़ों के दर्द में आराम

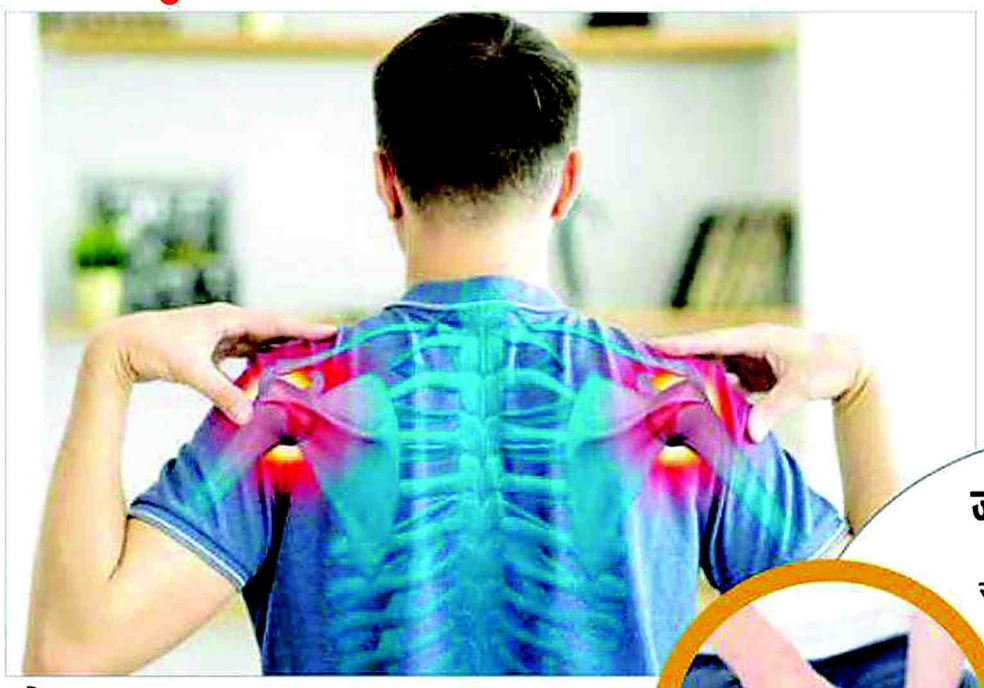

जोड़ों में दर्द की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। गठिया, हड्डियों में दर्द, सूजन और कुछ प्रकार की अन्य स्थितियों के कारण आपको जोड़ों में दर्द की दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं, जोड़ों में दर्द के लिए ऑस्टियोपोरोसिस-ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक बीमारी को प्रमुख कारण माना जाता है, समय के साथ इसका खतरा युवाओं में भी बढ़ता जा रहा है।

ऑस्टियोआर्थराइटिस तब होता है जब आपके जोड़ में आर्टिकुलर कार्टिलेज टूट जाते हैं। इन स्थितियों में जोड़ों की हड्डियां आपस में रगड़ती हैं और इस घर्षण के कारण तेज दर्द का अनुभव हो सकता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया लाइफस्टाइल-आहार में गड़बड़ी भी जोड़ों में दर्द को बढ़ाने वाली हो सकती है। अगर आपको भी अक्सर ये दिक्कत रहती है तो इस बारे में किसी विशेषज्ञ से मिलकर दर्द के कारणों का सही निदान जरूर करा लें। आइए जानते हैं कि किन घरेलू उपायों की मदद से जोड़ों के दर्द से आराम पाया जा सकता है?

नियमित व्यायाम और स्ट्रेचिंग का करते रहें अभ्यास

जोड़ों में दर्द के शुरुआती चरणों में नियमित व्यायाम और स्ट्रेचिंग की मदद से गठिया के सूजन को कम करने और जोड़ों के दर्द से राहत पाने में मदद मिल सकती है। स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव कम होता है और रक्त का संचार ठीक बना रहता है। मांसपेशियों में रक्त का संचार ठीक रहने से दर्द से आराम पाया जा सकता है।

हीट-कोल्ड थेरेपी

प्रभावित जोड़ों पर हीट-कोल्ड थेरेपी करने से भी दर्द और सूजन से अस्थायी राहत मिल सकती है। हीट थेरेपी जैसे गर्म पानी से स्नान या हीटिंग पैड से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है और मांसपेशियों की कठोरता कम होती है।

जबकि कोल्ड थेरेपी जैसे आइस पैक से सूजन और जोड़ों में होने वाले दर्द को कम किया जा सकता है। कोल्ड थेरेपी की मदद से दर्द वाले रिसेप्टर्स सुन्न हो जाते हैं। दर्द से आराम पाने के लिए ये उपाय भी काफी प्रभावी हो सकते हैं। ●

वजन को बढ़ने से रोकना जरूरी

अतिरिक्त वजन, घुटने और कूल्हे जैसे जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है, जिससे दर्द और सूजन बढ़ने लगती है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के माध्यम से वजन को कंट्रोल बनाए रखने में मदद मिल सकती है। जोड़ों पर पड़ने वाले तनाव और असुविधा को कम करने के लिए शरीर का वजन कम रखना जरूरी है। लाइफस्टाइल और आहार में सुधार करके जोड़ों की समस्याओं में काफी हद तक सुधार करने में मदद मिल सकती है।

जोड़ों में दर्द की समस्या

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं गठिया के कारणों और जोड़ों में दर्द के लक्षणों के आधार पर सभी लोगों के लिए इसके उपचार के तरीके भी अलग-अलग हो सकते हैं। आर्थराइटिस मुख्यरूप से दो प्रकार के होते हैं- इंफ्लामेटरी और नॉन-इंफ्लामेटरी। नॉन-इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस में बिना दवाओं के भी कुछ उपायों की मदद से लक्षणों में आराम पाया जा सकता है। यदि आपको भी अक्सर जोड़ों में दर्द रहता है तो इन उपायों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

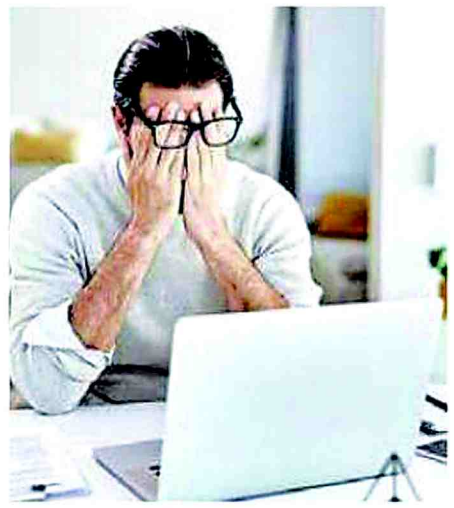

स्क्रीन टाइम बन रहा है साइलेंट किलर, बढ़ रहा है हार्ट की बीमारियों का खतरा

तकनीक के विकास के साथ-साथ हमारे जीवन में काफी बदलाव आए हैं। अब हमारा ज्यादातर काम स्मार्टफोन या लैपटॉप पर होता है। इसलिए हमारा स्क्रीन टाइम काफी बढ़ चुका है। लंबे समय तक स्क्रीन पर लगे रहने से हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य प्राभावित होता है।

ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से एक तरफ, जहां मानसिक स्वास्थ्य के साथ स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं, वहीं दूसरी तरफ शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, डायबिटीज और सबसे अधिक आंखों की रोशनी में कमी आने लगती है।

यहां तक कि सामाजिक संबंधों में कमी, क्रिएटिविटी में कमी और सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी कमी आने जैसी समस्याएं भी ज्यादा स्क्रीन टाइम का नतीजा हो सकते हैं। ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए स्क्रीन टाइम कम करना ही सबसे बेहतर विकल्प है। आइए जानते हैं-

दिल को कमजोर बना रहा है स्क्रीन टाइम

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक एक नॉर्मल और हेल्दी हार्ट में इलेक्ट्रिक सिग्नल धड़कनों को कंट्रोल करते हैं लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक संकेत बिगड़ जाते हैं तब दिल का ऊपरी हिस्सा सिकुड़ने के बजाय कांपने लगता है। इससे धड़कनों की रफ्तार बिगड़ जाती है।

युवाओं के हार्ट में बढ़ रही है ब्लॉकेज

इतना ही नहीं हार्ट की आर्टरीज ब्लॉकेज मिल रही है। जबकि पांच साल पहले तक ये ब्लॉकेज 1 से 2 सेंटीमीटर की होती थी। घबराने वाली बात ये है कि दिल के मरीजों में ब्लॉकेज की परेशानी दिख रही है। हार्ट में बढ़ती ब्लॉकेज चिंताजनक है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है।

इसलिए होते जा रहे हैं कमजोर

टारगेट का प्रेशर

कंप्यूटर और लैपटॉप पर घंटों काम करना

पैकेट बंद मार्केट का खाना

फिजिकल एक्टिविटी कम होना

कैसे करें बचाव?

बीपी के मरीज नियमित रूप से दवा खाएं

रोजाना 30 मिनट का कोई भी व्यायाम करें

तला भुना ज्यादा न खाएं

पिज्जा बर्गर और जंक फूड से दूर रहें

काम का प्रेशर कम रखें

तनाव कम से कम लें ●

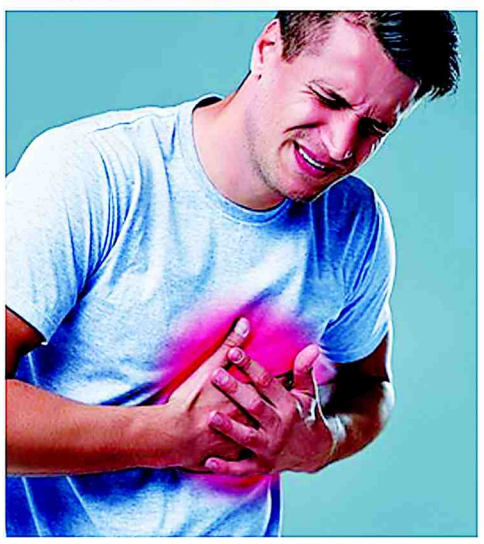

अगर आपका बच्चा लगातार छींकता है तो इस तरह रखें उनका ख्याल

आपका बच्चा अगर लगातार छींकता है तो आपको पता चल जाता है कि उसे जुकाम हो गया है। उसे सचमुच ऐसा हुआ है या नहीं, इसका आपको पता नहीं चलता। क्योंकि हर बच्चे की बीमारी के लक्षण अलग-अलग होते हैं। मुद्दा यह है कि बीमारी उसे या तो अपना शिकार बना लेती है या आप उसे बीमार होने से बचा लेते हैं। दरअसल यह उसके पोषण के स्तर पर भी निर्भर करता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं : प्रोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह बच्चे की कोशिकाओं के पुनर्निमाण में भी सहायक होती है। इसलिए उसके लिए सही प्रोटीन का चयन करना जरूरी है। अंडे के सफेद भाग में या सफेद मीट के अलावा फिश, दाल और मोटे अनाज में मौजूद प्रोटीन का उसे फायदा मिल सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में विटामिन-सी की भी भूमिका कम नहीं है। यह आंवला, कीवी और मल्टी विटामिन में होता है लेकिन जो भी खाएं डॉक्टर के निर्देशानुसार खाएं।

बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में विटामिन बी12 की भूमिका की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। बच्चे के बीमार होने पर यह उसे जल्दी रिकवरी देता है। शाकाहारियों के लिए तो यह विटामिन एक वरदान है। यह मूल रूप से एनीमल प्रोडक्ट्स जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडों में पाया जाता है। बच्चों को शिशु रोग विशेषज्ञ के निर्देशानुसार विटामिन-बी12 के सप्लीमेंट्स भी दिये जा सकते हैं।

बदलता मूड : कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे के मूड में बार-बार बदलाव होता है। हो सकता है वह दादा-दादी के प्यार की वजह से बिगड़ा हो और मूड स्विंग उसके व्यक्तित्व का हिस्सा न हो लेकिन इसकी जड़ें उसके ग्लूटेन इंटोलरेंस में भी हो सकती हैं। अब सवाल है इसका पता कैसे लगाया जाए? इसके लिए उसके भोजन से ग्लूटेन को बाहर करें और उसके बाद भी अगर उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होता तो समझें कि ऐसा नहीं है। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि इन चीजों के द्वारा उसके मानसिक स्वास्थ्य को जाना जा सकता है लेकिन इलाज से परहेज बेहतर है। छुट्टियों में या परीक्षा के दिनों में उसे स्मार्ट इटिंग द्वारा पोषण दिया जा सकता है। अब अगर सब्जियों और फलों का पोषण उसकी प्लेट में यूं ही सजाया जा सकता है तो सप्लीमेंट्स पिल्स लेने की क्या जरूरत है? कुल मिलाकर अपने बच्चे को प्राकृतिक तरीके से भी आप स्वस्थ रख सकते हैं। ●

घर में इस तरह रखें लाफिंग बुद्धा

कुबेर भगवान को जिस तरह से हिंदू धर्म में धन वृद्धि का प्रतीक माना गया है वैसे ही शुभ और धन समृद्धि लाने के लिए लाफिंग बुद्धा को चीन में यही दर्जा दिया गया है। लाफिंग बुद्धा की यह मान्यता कही लोगों में दिखाई देती है जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर में लाफिंग बुद्धा रखे हुए हैं।

लेकिन क्या आपको पता है कि कहीं पर भी लाफिंग बुद्धा को रखने से शुभता और धन-समृद्धि नहीं आती। सही दिशा और स्थान पर लाफिंग बुद्धा को रखा जाता है जिसके बारे में आपको पहले पता होना आवश्यक है। घर में जिस तरह से आपको जरूरत है उसी दिशा में लाफिंग बुद्धा को रखा जाता है।

परिवार के भाग्य और सुख शांति के लिए घर की पूर्व दिशा को माना गया है। एक लाफिंग बुद्धा आप अपने घर के पूर्व दिशा में रखते हैं तो इससे परिवार के सदस्यों के

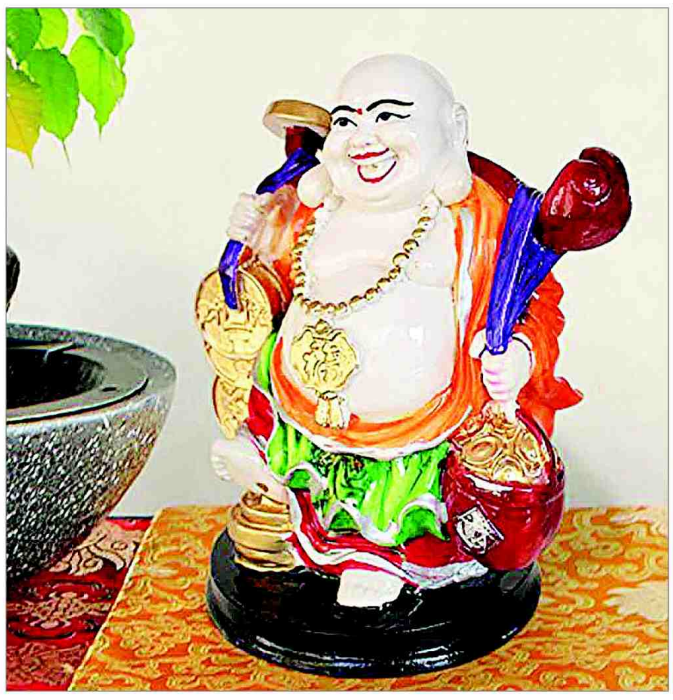

बीच प्रेम और तालमेल बना रहता है। ध्यान रहे कि पूर्व दिशा में दोनों हाथों को उठाए हंसते हुए लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए। फेंगशुई में बताया गया है कि घर में दक्षिण पूर्व दिशा में लाफिंग बुद्धा को रखने से सकारात्मक ऊर्जा उस जगह की बढ़ती है साथ ही जीवन में धन और सुख का लाभ होता है। इस दिशा में लाफिंग बुद्धा रखने से घर के सदस्यों की आमदनी में भी बढ़ोतरी आती है। इतना ही नहीं अगर आपको विरोधी नौकरी व्यवसाय में परेशान कर रहे हैं तो इससे भी राहत मिलती है।

ऐसा कहा जाता है कि घर या दफ्तर में लाफिंग बुद्धा अपनी आंखों की ऊंचाई के बराबर रखना चाहिए। मतलब यह है कि जैसे ही आप आएं तो आपकी सीधी नजर लाफिंग बुद्धा पर पड़े। ध्यान रहे कि लाफिंग बुद्धा को ज्यादा ऊंचाई या नीचे नहीं रखें।

हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि दरवाजे की तरफ गणेश जी का मुंह होना शुभ होता है उसी तरह से लाफिंग बुद्धा का भी मुंह दरवाजे की तरफ होने से धन और समृद्धि का आगमन जीवन में होता है।

इन राशि के लोगों को नहीं पहननी चाहिए चांदी की अंगूठी

कई सारे लोग सोने और चांदी के आभूषण पहनने के बहुत शौकीन होते हैं। तो वहीं इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये अभूषण विद्वान पंडित की सलाह से पहने होते हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र की मानें तो चांदी के आभूषण खूबसूरती बढ़ाने के अलावा सुख-समृद्धि का भी कारक माना जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक चांदी नौ ग्रहों में शुक्र और चंद्रमा ग्रह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि चांदी की उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्रों से हुई थी और जिस जगह भी चांदी होती है उस जगह सुख, वैभव और संपन्नता में जरा भी कमी नहीं आती है। इन सारी चीजों के अलावा ज्योतिष शास्त्र में ये भी बताया गया है कि चांदी की अंगूठी पहनना सभी के लिए अच्छा नहीं होता है।

तो ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि चांदी की अंगूठी किस राशि के लोगों को नहीं पहननी चाहिए।

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मेष, धनु और कन्या राशि के जातकों को चांदी की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। इन राशि के लोगों के लिए चांदी की अंगूठी धारण करना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि ये लोग चांदी की अंगूठी हाथ में धारण कर लेते हैं तो इनके लिए ये अशुभ साबित होगा और ये इन जातकों के लिए दुर्भाग्य की वजह भी बनती है।

माना जाता है कि इसे पहनने से परिवार के लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है और स्वास्थ्य संबंधित संकट भी बने रहने का डर होता है। इसके अलावा इनके जीवन में चांदी की अंगूठी पहनना असफलता का कारण भी बन सकती है।

वास्तु के ये नियम धन को करते हैं आकर्षित

शास्त्रों की मानें तो भगवान कुबैर धन के देवता है। कहा जाता है कि अगर कुबैर भगवान को खुश रखेंगे तो घर में पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय बताए गए हैं। इन नियमों को अपनाएंगे तो घर में पैसों की परेशानी नहीं होगी।

घर में प्रवेश द्वार के कारण ही पैसा आता है। इसलिए अपने घर के प्रवेश द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर का प्रवेश द्वार खुशियों और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर आप एक घंटी या विंड चाइम्स लटका सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि इस की आवाज पैसों को आकर्षित करती है। इसके अलावा

घर के मुख्य द्वार के सामने अपने घर में एक सुंदर सा लैंप लगाएं और इसे जलाएं। कहा जाता है कि लाल, वायलेट और हरा रंग धन को आकर्षित करता है। इसलिए घर में इस रंग का कलर करा सकते हैं। इसके अलावा आप फर्नीचर, एक्सेसरीज में भी इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सोना धन और वैभव का प्रतीक है। इसलिए घर में गोल्ड के कलर की कोई चीज जरूर रखें, जैसे गोल्डन एक्सेसरीज।

घर का किचन आपके लिए मुख्य ऊर्जा का हिस्सा है। यह आपके जीवन की खुशियों और समृद्धि के लिए जिम्मेदार है। इसलिए किचन को साफ रखें अच्छे तरीके से किचन की चीजों को रखें।

घर में चीजों को इस तरह रखें कि स्पेस ज्यादा रहे। घर में बिना वजह का कबाड़ न रखें। सकारात्मक एनर्जी इसी तरह आएगी।

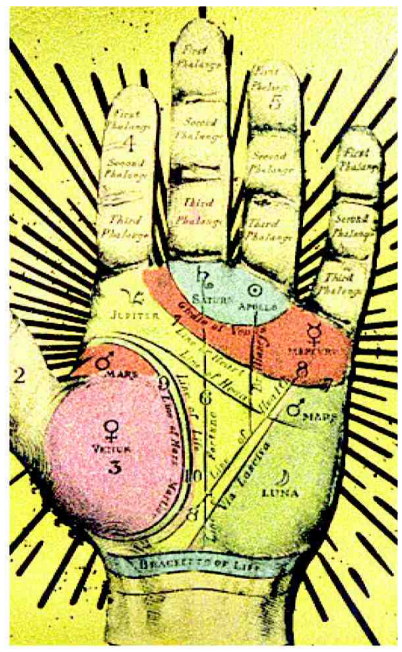

जिनकी हथेलियों पर बनते हैं ऐसे निशान वो लोग होते हैं भाग्यशाली

सामुद्रशास्त्र में व्यक्ति के भविष्य में होने वाली अच्छी और खराब बातों का संकेत उनके हथेली पर बने कुछ खास तरह के निशान और चिन्ह बताते हैं। इन संकेतों के बारे में आप हस्तरेखा शास्त्र में पढ़ सकते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता पहले लगा सकते हैं। शास्त्रों में विस्तार से वर्णन हमारी हथेली में बनी आकृतियों और रेखाओं के बारे में बताया गया है। हथेली की इन रेखाओं से पता चल जाता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है या नहीं। हृदय रेखा, जीवन रेखा, विवाह रेखा और भाग्य रेखा हमारी हथेली पर बनी होती है। व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं से इन रेखाओं और आकृतियों का संबंध जुड़ा होता है।

मणिबंध से जिन व्यक्ति की भाग्य रेखा शुरू होती है और शनि पर्वत पर सीधे जाकर मिलती है। इन व्यक्तियों का भाग्य बहुत भाग्यशाली होता है। हर क्षेत्र में इन व्यक्तियों को सफलता प्राप्त होती है। इतना ही नहीं यह हार भी बिल्कुल नहीं मानते हैं। इन व्यक्तियों के जीवन में जब भी समय विपरीत चलता है तो यह धैर्य और संयम बनाए रखते हैं।

भाग्य रेखा चंद्रमा के क्षेत्र से जिन व्यक्ति की हथेली पर प्रारंभ होती है। वह अपने हर काम में सफल होते हैं और मान-सम्मान उन्हें जीवन में खूब मिलता है। इस हस्तरेखा के लोगों को अपने मान-सम्मान का बहुत ध्यान होता है और यह छोटे बड़े हर इंसान के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं।

जीवन से प्रारंभ होती है जिन व्यक्ति की भाग्य रेखा तो उनके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां नहीं आती हैं। आर्थिक पक्ष इन लोगों का बहुत बेहतर होता है। धन-धान्य से परिपूर्ण इन लोगों का जीवन हमेशा रहता है।

साप्ताहिक समय माया

पीएम मोदी का बिल बकाया!

पेज 1 का शेष

मैसूर में रेडिसन ब्लू प्लाजा में प्रधानमंत्री के दल के ठहरने से संबंधित खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इसके बाद, 22 मार्च, 2024 को एक और पत्र वर्तमान पीसीसीएफ सुभाष के. मालखेड़े द्वारा लिखा गया था, जिसमें एनटीसीए को बकाया राशि की याद दिलाई गई थी, जिसमें रेडिसन ब्लू प्लाजा में प्रधान मंत्री के ठहरने के दौरान करीब 80.6 लाख के होटल बिलों का भुगतान न करना भी शामिल था, लेकिन वहां अभी तक कोई जवाब नहीं आया।

इरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के काफिले का हेलिकॉप्टर क्रैश हादसा या साजिश..?

पेज 1 का शेष

...फिलहाल, वास्तव में किसी भी बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन, मैं कहूंगा कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह पूरी तरह से मौसम से संबंधित था और शायद एक तकनीकी खराबी थी जिसके कारण हेलिकॉप्टर नीचे गिर गया। और उस प्रकार के इलाकों में, यदि हेलिकॉप्टर नीचे आता है, तो आप वास्तव में कठिन लैंडिंग नहीं कर सकते।

ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए आपको भाग्यशाली होना होगा। 'यह हर किसी के लिए थोड़ा आश्चर्य और सदमे जैसा था। लेकिन, यह देखते हुए कि मौसम उस विशेष क्षेत्र, इलाके में था। यह बहुत संभव है कि यह एक दुर्घटना थी'

उन्होंने आगे चर्चा की कि इस दुर्घटना का ईरानी व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा; उनके शब्दों में, 'यह सिर्फ एक त्रासदी है जो ईरान में आई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका वास्तव में ईरानी व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि कट्टरपंथियों का नियंत्रण बहुत मुकम्मल है. रायसी एक कट्टरपंथी थे, कुछ लोगों का दावा है कि वह सर्वोच्च नेता के उत्तराधिकारी बनने की कतार में थे, और अब वह चले गए हैं, शायद सर्वोच्च नेता का स्पष्ट उत्तराधिकारी बनने के लिए उस स्तर पर दौड़/संघर्ष होने वाला है'

ईडी सीबीआई लोकायुक्त सभी जांच एजेंसियां बिकाऊ चाहिए खरीददार

पेज 1 का शेष

जब चारों तरफ से घिर जाते हैं. तो वह प्रतिनियुक्ति पर इन संस्थानों में चले/भेज जाते हैं।स्वाभाविक है चोर चोरी से जाएं हेरा फेरी से न जाए। तो फिर वे अपने आकाओं के इशारे पर नाच कर जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। 100 करोड़ पकड़ते हैं। तो 10 करोड़ दिखाते हैं 90 करोड़ हजम कर जाते हैं। वहां कोई देव पुरुष नहीं बैठे होते हैं। सब छंटे हुए विभिन्न राज्यों के पुलिस विभाग के मोटी चमड़ी के चुने हुए पुलिस कर्मी निरीक्षक ही होते हैं।

एक बार में लोकायुक्त कार्यालय गया जो सीधे एसपी से मुलाकात हुई उसने मुझ से बातचीत बोला कि अजमेरा साहब आप 3-4 घंटे के लिए हर दिन हमारे कार्यालय आ जाया करो। तुम मैंने बोला मुझे क्या आता है यहां पर कार्यालय में आकर क्या करूंगा उसने मेरे को मेरी कहानी सुना दी। बोले आपके बारे में हमें सब कुछ मालूम है। आप चार्टर्ड व कास्ट अकाउंटेंसी के स्टूडेंट रहे हैं। आपने एल एल बी के साथ श्रम कानूनो बैंकिंग की डिग्रियां ली हैं। आयुर्वेद होम्योपैथी पढ़ी है। आपके पास कई विषयों का ज्ञान है। आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे मे भी छापते रहते हैं। बैंक में नौकरी की है। आपने बैंक की नौकरी में जो डेढ़ दो साल में बैंक ऑफ़ इंडिया के मुख्यालय को जो सजेशन भेजे थे। उस पर पूरी दुनिया की बैंकिंग इंडस्ट्री में भारी बदलाव लाने के साथ आपके कुछ ब्याज के फार्मूले पर दुनिया के बैंक के कंप्यूटर चल रहे हैं। आपके पास अधिकांश विभागों की तकनीकी जानकारी रहती है। आपने हवाई जहाज भी उड़ाया है। तो मैं चोंक गया।तो मैने पूछ लिया कि क्या मेरी भी जासूसी भी करवाई जाती है। तो वे बोले नहीं। आखरी में मैं पूछ लिया कि आप तो बताइए कि आपका क्या काम है? बोले तो बोल कि हम तीन-चार साल पहले एक छापे में किसी अधिकारी यहां से शेयर डिबेंचर बॉन्ड एन एस सी जप्त करके लाए थे। तो मैं पूछ लिया कि आपने उनका क्या किया तो बोले वैसे के वैसे फाइलों में अलमारी में रखे हुए हैं। मैंने पूछा उसके बाद मेंबोले नहीं रखे हुए हैं मैने पूछा ट्रांसफर कारवाये की नहीं। जिसने उनको जारी किया था। उनको सूचित किया कि नहीं किया। तो बोले नहीं।

मैंने बोल दिया कि उसने सबके घूमने चोरी होने का शपथ पत्र देकर डुप्लीकेट निकलवा कर सब बेंच दिए होंगे। सबका पैसा खड़ा कर चुका होगा और आपके पास वह सारे के सारे और रद्दी के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। यह सच घटना सन 2006 में इंदौर के लोकायुक्त कार्यालय में ही घटी थी। इस घटना आप समझ सकते हैं उनके ज्ञान और बुद्धि को।

ऐसे ही आई ए एस यह हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवायथार्थ में भारतीय प्रताणना सेवा होती है। बस एक बार जीवन में साल 2 साल की कड़ी मेहनत करके परीक्षा पास कर लेने व सफल होने के बाद यह देश के 30 से 45 साल तक के लिए खुदा बन जाते हैं।

अब इस बात से अंदाज लगाइए कि एक कलेक्टर के पास देश के 400 कानूनों में कार्रवाई करने निर्णय देने व्याख्या करनेऔर उसे पर दंडात्मक कार्रवाई करने तक के अधिकार होते हैं। वह जिले का भारत सरकार की तरफ से सचिव भी होता है। जिसके पास जिले के 100 से ज्यादा विभागों का नियंत्रण संरक्षण वसूली देखरेख निर्णय देने निर्देशित करने काम करवाने का क्षेत्राधिकार होता है।

इसलिए जिले का सरकारी पोस डकैत कहता हूं। इसके विपरीत ना तो उसने कानून की पढ़ाई की होती है और ना परीक्षा पास की होती है। पर हर दिन अनेकों वकीलों की दलीलें सुनना बहस करना और निर्णय देने का काम इस आजाद भारत में पिछले 75 साल से बिना कानून की डिग्री लिए निर्णय देने का काम हो रहा है। अब आप सोच लीजिए कि उसने कितने कानून पढ़े होंगे? कितने याद रहते होंगे?

यथार्थ में उसे कुछ भी याद नहीं रहता उसे केवल नोट और जो बाबू ने सिखा पढ़ा दिया समझा दिया उस पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त इन हरामखोरों को भी केवल प्रताड़ना देना वसूली करने के अलावा क्या आता है? कहानी लंबी खिंच गई है पर सच और भी गहरा है।

युवा मित्रों को इसलिए बताया जा रहा है। ताकि वह किसी भी तथ्य पर बत करने से पहले कानून का अध्ययन कर उसको लपेट देंगे तो कोई भी आईएएस आईपीएस आईएफएस चुप हो जाएगा। अर्थात कानून की आड़ में लूट और डकैती करने में आईएएस आईपीएस आईएफएस सरकारी डकैत होते हैं।

शिक्षा में प्रवेश से परीक्षा तक लूट डकैती का तांडव

पेज 8 का शेष

इसके कारण उसका शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं हो सकेगा और यही सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़ेगे ही नही तो अनपढ़ गवारों को मजदूर बंधवा मजदूरों की भांति कैसे भी हां का जूता जाकर अपनी सत्ता को दीर्घकाल तक बनाए रखने में किसी भी बड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अनपढ़ गवार जाहिलों को जो जैसा सरकार बने पढ़ाई की समझाएगी बताएगी उसको वैसा ही मानना अनपढ़ों की मजबूरी होगी आप जब शिक्षित युवा होंगे ही नहीं तो नौकरी मांगने हल्ला मचाने सरकार को बदनाम करने सरकार से प्रश्न करने का भी कोई सवाल ही नहीं उठेगा हाल ही में अब जब देश की 80% जनता दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है शिक्षण संस्थानों में पूरे साल भर की 80% फीस जमा करने का नया फरमान जारी कर दिया गया है इसके संबंध में दैनिक भास्कर ने छापा है।

चुनावी मतों की गिनती में पूरी जालसाजी एक्सेल शीट बनती ही नहीं

हर कक्ष, सभी कक्षों व हर व सभी चक्रों की हर सीट की एक्सेल शीट की जाए अपलोड

सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए की चुनाव आयोग से लेकर राज्यों के चुनाव आयोग से जिलों के चुनाव अधिकारी कलेक्टरों व सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव करवाने वाले कर्मियों तक को डरा धमका कर न केवल भाजपा के नेताओं द्वारा फर्जी वोट डलवाने के साथ-साथ केंद्रों पर ही अंत में भारी फर्जी वोटिंग करवा कर प्रतिशत बढ़ाया गया है।

इसीलिए 90% से ज्यादा मतदान केंद्रों पर सीसी और वेब कैमरों की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जबकि सबके झूठे बिल पूरे देश में लगाकर लगभग हजार करोड रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार जिलों के कलेक्टरों द्वारा किया जा रहा है।

इंदौर में ही वास्तविकता में 30-35% से ज्यादा कहीं वोटिंग नहीं हुई। जैसी कि मेरी अनेकों केदो के मतदान कर्मियों से चुनाव बाद चर्चा हुई। पर उसको 60% दिखा तीन दिन बाद भास्कर ने 80% वोटिंग छाप दी।

मेरे सच को जानने के लिए देश के चुनाव आयोग से लेकर राज्यों के चुनाव आयोग व जिलों के कलेक्टर के साथ सभी मतदान कर्मियों के मोबाइल फोन की बातचीत की रिकॉर्डिंग से सारे मतदान के फर्जी वाड़े का सच जाना जा सकता है ।

यह कहानी का एक हिस्सा है। सबसे बड़ी जालसाजी मशीन खोलकर मतगणना करने के समय होती है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सन 2014 और 19 में मशीन शाम को 6:00 बजे तक खोली जाती रही और चुनाव जीतने की घोषणा 2:30 बजे ही कलेक्टर और एसडीएम ने एक अलग कमरे में बैठे एसडीएम ने बड़े चार्ट पर अपने मन से वोटिंग दिखाकर कर दी।

यथार्थ में मशीन खोलकर गिनती करने का पूरा अलग, बहुत बड़ा भारी फर्जीबाड़ा होता है।

यदि सच्चाई के साथ हर मशीन खोलकर हर कक्ष की कुल मशीनों के हर उम्मीदवार के योग की, फिर सभी कक्षों के हर चक्र के हर उम्मीदवार के कुल योग की, अंत में सभी कक्षाओं के सभी उम्मीदवारों के सभी चक्रों की सकल योग की, और अंत मेंसभी उम्मीदवारोंके सभी कक्षाऑन के हर चक्र और सभी चक्रवके शक्ल महायोग की क्लासीफाइड एक्सेल शीट बनाई जानी चाहिए।जिसमें किसी भी लोकसभा चुनाव में काम से कम 24 से 30 घंटे लगेंगे। परंतु यहां तो किसी की एक्सेल शीट बनाई ही नहीं जाती और चुनाव मशीन

सर्वोच्च न्यायालय को चुनाव आयोग को आदेशित कर हर सीट की गिनती की एक्सेल शीट को आयोग की साइट पर सार्वजनिक करे

खोली जाती रहती हैं सीट बनती रहती हैं और हर शीट दिखा कर अंत में टोकरी में फेंक दिया जाकर वह अपने मन से ही ढाई तीन 4:00 बजे तक एक तरफा भाजपा के उम्मीदवारों को जिताने की घोषणा कर दी जाती है।

जबकि देश की 80% सीटों से ज्यादा पर प्रति लोकसभा 30 से 35 लाख जनता होती है जिसके 50% वोट भी साडे 17 18 लाख होते हैं। अधिकांश जगह 5 से 15 उम्मीदवार होते हैं।

मेरा इस संबंध में निवेदन है, की आने वाले 4 जून को होने वाली गिनती में हर कक्ष में जहां 10 से 12 टेबल होती हैं। हर टेबल पर जिसमें 10 से18-20 मशीन खोली जा कर हर मशीन की हर उम्मीदवार की प्राप्त मतों की सूची बनाई जाती है। जिसे तत्काल में हर मशीनों टेबल की एक्सेल शीट डाला जाना चाहिए जो कभी कहीं नहीं डाला जाता और इसीलिए यह सारे जलशा भ्रष्ट कभी भी एक्सचेंज की कॉपी उम्मीदवार को ना तो उसके अधिकार में देते हैं और ना ही सूचना के अधिकार में देते हैं। तो हर टेबल पर कैमरा होने के साथ-साथजो भी कंप्यूटर एक्सेल शीट बनाएगा वह फिर जिस कमरे में सभी कमरों के सभी टेबल की हर उम्मीदवार कीकल व सकल योग की एक्सेल शीट बनाई जाएगी उसकी कॉपी की गणना केवल कैमरे बल्कि वेब कैमरे परदेश और दुनिया की जनता को पारदर्शिका से गिनती होने के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में दिखाई जानी चाहिए जिसके लिए हर राउंड को पूरा करने में लगभग 2 घंटे पूरे लगेंगे। जहां 18 से 20 राउंड की काउंटिंग है वहां नेट दो से तीन दिन लगेंगे। अर्थात 18 राउंड की काउंटिंग में यदि 15 उम्मीदवार खड़े हुए हैंतो लगभग36 से60 72 घंटे तक लग सकते हैं। कलेक्टर काउंटिंग से पहले घोषणा करता है कि हर कक्षा की हर मशीन कंप्यूटर से जुड़ी हुई है पर कभी भी जुड़ी हुई देखी गई कभी भी एक्सेसिविटी मनाई जाती सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन है कि देश में जो 4 जून को मतगणना होगी वहां की हर मशीन की गणना की कॉपी के साथ हर कमरे के हर चक्र की और सभी कमरों के हर चक्र की फिर सभी कमरों के सभी चक्रों की कलश क्लमा और महाशक्ल योग के एक्सेल शीट की कॉपी को वेब कैमरे पर गिनती होते हुए दिखाएं और सभी लोकसभा सीटों की सारी एक्सेल सीट चुनाव आयोग अपनी साइट पर हर मशीन के उम्मीदवारों के साथ कमरे के सभी टेबलों की हर चक्र के कुल योग की, फिर सभी कमरों के हर उम्मीदवार को मिले मत पत्रों के हर चक्र के कुल सकल योग की, और अंत में सभी कमरों के सभी चक्रों की हर उम्मीद पर के हिसाब सेकुल सकल महायोग की कॉपी अपनी साइट पर प्रदर्शित करें इस ईमानदारी पूर्ण कार्य करने में लगभग न्यूनतम 24 से 72 घंटे तक लगा सकते हैं। जिसका प्रदर्शन हर लोकसभा के हिसाब से चुनाव आयोग के प्रतिनिधि कलेक्टर को चुनाव आयोग की साइट पर ईमानदारी और पारदर्शिता से करना ही चाहिए। जो उम्मीदवारों के साथ देश की 125 करोड़ जनता का भी हक है।

जो भी पाठकमेरे स्तर से सहमत हो वह चुनाव आयोग के साथ सर्वोच्च न्यायालय के ईमेल supremecourtofindia@nic.in, presidentofindia@nic.in पर अवश्य भेज कर मांग कर सकते हैं।

बेशक पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र में कलेक्टर को डरा धमका कर10 से 20% वोटिंग बढ़वाने के साथ क्योंकि मशीन पहले दूसरे चरण की महीने भर से ज्यादा समय से स्ट्रांग रूम में रखी है।

हर स्ट्रांग में अंदर से भी आने को रास्तेहोते हैंबाहर भले ही तारा मटका हुआ हो और उम्मीदवारों की प्रतिनिधि बैठे हुए हो उससे कुछ नहीं होता।

सारे वोट बदल दिए गए हैं क्योंकि मशीन के ऊपर सील लगाई जाती है जबकि उसके चार्जिंग पोर्ट के साथ प्रोग्रामिंग पोर्ट भी खुले रहते हैं। जिसे यूएसबी केबल से कनेक्ट करने के साथ मोबाइल से कनेक्ट करके उसकी कमान्ड देकर बदला जा सकता है। और वह बदल दिया गया है। इसीलिए मोदी शुरू से 400 400 पार कर रहा है। लेखक निवेदक एवं प्रस्तुत करता स्वयं दो बार लोकसभा और एक बार महापौर चुनाव इंदौर में इसीलिए लड़ चुका है। ताकि निकट से जालसाजी का सच देखा जा सके। चुनाव यथार्थ में जनता को भ्रमित करने और कलेक्टर सरकारी अधिकारियों की सैकड़ो करोड़ की मोटी कमाई का मोटा साधन है।

स्कूल आफ एक्सीलेंस फार आइज भी जालसाजों का अड्डा

चक्षु विशेषज्ञ के स्थान पर अस्थि विशेषज्ञ घोर भ्रष्ट डीके शर्मा प्रभारी

एमजीएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की साइट mgmmcindore.in
सालों से अपडेट नहीं भ्रष्टाचार छुपाने कई जानकारियां वर्षों पुरानी

मध्य प्रदेश का पुराना महाराजा यशवंत राव होलकर चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जिसे अब महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदोर एवं महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के नाम से जाना जाता है अपने आये दिन होने वाले भ्रष्टाचारों के लिए समाचार पत्रों मेंअपना स्थान ग्रहण करता रहता है। वर्तमान में कोरोना के समय ज्योति बिंदल को कोरोना का मेरा बताया सच ठीक कोरोना बदलते मौसम में होने वाली सर्दी खांसी की बीमारी है को बता देने के कारण तत्काल विश्व घातक संगठन एवं उसके भारतीय प्रतिनिधि संस्थाएं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कहने पर 26 27 मार्च 2020 को हटाकर वर्तमान में बैठे संजय दीक्षित को वहां का डीन या अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी बना दिया गया था परंतु अभी तक साइट पर डा. ज्योति बिंदल कुछ पीडीएफ फाईलों में डीन के रूप में ही दिखाई जा रही हैं। क्योंकि एमजीएम मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा भ्रष्टाचार डकैती का अड्डा है। इसलिए ना तो उसमें विभिन्न फैकल्टी के नाम के साथ उनके प्रोफेसर लेक्चर दिए हुए हैं। ना ही वहां काम कर रहे सभी प्रोफेसर लेक्चरार अधिकारियों कर्मचारियों के नाम की कोई सूची उनकी शिक्षा जन्म तिथि सेवानिवृत्ति की तिथि केवल जालसाजियों को कोई पकड़ा ना सके और उसमें हल्ला ना मुझे इसलिए नहीं डाली गई है अब आप इस बात अंदाजा लगा लीजिए की डा डीके शर्मा अस्थि रोग विशेषज्ञ है। परंतु वे स्कूल आफ एक्सीलेंस फॉर आइज के प्रभारी अधिष्ठाता बनकर भ्रष्टाचार करने और लूटने के लिए बैठे हुए हैं। अधीक्षक के रूप में स ठाकुर जैसा की साइट बता रही है विराजे हुए हैं जिनके कार्यकाल में खरीदी निविदाओं के करोड़ों के घोटाले हुए। भास्कर ने भी प्रकाशित किया था कि किस प्रकार गसी स्कूल आफ एक्सीलेंस फॉर आइज में रोगियों से बिना शासकीय रसीद दिए फर्जी रसीदों पर यह हरामखोर जलसा खुलकर वसूली कर रहे हैं। अधिकांश स्टाफ ठेके पर लगाया गया है और ठेके सुपरवाइजर के रूप में वहां बैठा अमन शिंदे वहां उसके अंतर्गत बाह्य कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले युवा और युवतियां जिनका वहां भारी भूषण किया जा रहा है और यह हरामखोर रमन शिंदे जो उनके खास होते हैं वह तीन तीन चार-चार दिन छुट्टियां मनाते हैं तो भी उन्हें 15-16000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है और जो इनके खास नहीं होते हैं उनसे 8 घंटे के स्थान पर 12-12 घंटे काम लिख दिया जाता है और काम ही नहीं डीके शर्मा कुछ बच्चों को अपने घर पर साफ सफाई बर्तन भांडे मंजवाने लिपाई पुताई सफाई करवाने इसके लिए भी खुलकर प्रयोग कर रहे हैं आश्चर्य वाली बात तो यह है की मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग प्रधान सचिव से लेकर युक्त संयुक्त संचालक जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से नीचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक वहां बैठे डॉक्टरों की जनता के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के नाम पर हर्बर्ट्स कम से कम कुल कुल प्राप्त होने वाले विभिन्न योजनाओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग जो 40 से 50000 करोड रुपए मिलता है उसमें 15 से 20000 करोड रुपए का भ्रष्टाचार करके हजम कर लिया जाता है और यही कारण की है हरामखोर जालसाज विभाग अपने स्वास्थ्य विभाग की साइट पर कहीं पर भी पूरी जानकारी नहीं देता और इस विभाग के चाहे वह मेडिकल कॉलेज के होया सामान्य चिकित्सालयों के सभी विभागों के चिकित्सक अधिकांश हरामखोर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेने के बाद में भी अपनी निजी चिकित्सा करने के साथ-साथ अधिकांश समय सरकारी चिकित्सालय में उसे गायब रहकर निजी क्षेत्र के चिकित्सालय में अपनी सेवाएं देकर मोटी कमाई कर रहे हैंपर उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। जितने भी चिकित्सालय में मध्य प्रदेश भर में बाह्यठेका कर्मियों को नियुक्त किया गया है उनके नाम पर भी 20 से 25% कर्मचारियों को कम रखकरपूरा पैसा हजम करने के साथ-साथ वहां कार्य कर रहे कर्मचारियों का वहां के डॉक्टर व अधिकारी अपने घरों पर काम लेने से लेकर अन्य प्रकार से भी भारी शोषण कर रहे हैं। और उनके जो भी वहां के सुपरवाइजर जितने भी उन सब बाह्य कर्मचारी सुरक्षा कर्मियों की हाजिरी लगाते हैं। वे भी वहां पर आम साधारण युवाओं को 8 से 12 घंटे काम लेकर भी उनको हाजिरी ना देना, महिलाओं का यौन शोषण करना आदि करने के बाद में भी तीन छह महीने तक भुगतान नहीं देते हैं इसके बारे में श्रम अधिकारी भी अपना महीना वसूली कर चुपचाप रहते हैं।

जब वहां के प्रभारी डॉक्टर से इसकी शिकायत की जाती है तो मालूम पड़ता है। की सरकार से संबंधित ठेका कंपनी को भुगतान हो चुका है परंतु वह ठेका कंपनी ने उसे पैसे को कहीं और निवेशित करके उसका भरपूर सदुपयोग कर रही है और बच्चों को दोनों तीन महीने तक वेतन नहीं देती है।

स्वास्थ्य विभाग अपनी खरीदी और लापरवाही पूर्ण इलाज करने के लिए कुख्यात होने के साथ-साथ अधिकांश सरकारी डॉक्टर दलालों की भूमिका निभाते हैं और जहां वह प्राइम निजी सेवाएं देते हैं उन अस्पतालों की तरफ सरकारी अस्पतालों में आए मरीज को भेजने के लिए बाकायदा दवाई छोड़कर रखते हैं और उनसे मोटी कमाई करते हैं इसलिए जानबूझकर सभी सरकारी अस्पतालों में लगी हुई सभी प्रकार की मशीन यह था इसके नहीं बीपी ब्लड बैंक इको सोनोग्राफी आदि सभी प्रकार की मशीनों पर वहां कार्य डॉक्टर जहां विधि की सेवाएं देते हैं वहां के मरीजों काइलाज करके पैसे बसूलते हैं। जब किसी प्रकार की कोई उंगली उठती है तो जानबूझकर यह हरामखोर वहां के कर्मचारी अधिकारी डॉक्टर उन सरकारी मशीनों को खराब कर मरीजों को निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों में भेज कर वहां मरीजों को लूटवाने का षड्यंत्र भी करते हैं।

वर्तमान में एलोपैथिक सरकारी व निजी चिकित्सालयों मैं अधिकांश लूट डकैती के कसाइयों के अड्डे बन चुके हैं। और उन पर रोज ही कहीं ना कहीं लूट डकैती और जल साजो के कारण लड़ाई झगड़े की नौबत निजी और सरकारी दोनों में ही आती है सरकार का कानून इतना ढीलाहै कि अधिकांश डॉक्टर हर बार बच जाते हैं दूसरी तरफ अधिकांश निजी चिकित्सालयों में नेताओं अधिकारियों का पैसा लगा होता है इसलिए बीमारों व उनके संरक्षकों के साथ लूट डकैती होती रहती है। पर कोई कुछ नहीं बोलता और यही सब जिस चिकित्सक को लोग भगवान मानते हैं। कसाइयों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। इन सबका इन चिकित्सकों की लालची नियत के कारण यह हाल है।

विद्युत कंपनियों में कब रुकेगा मौतों का तांडव

बाह्य ठेका कर्मियों को ना प्रशिक्षण न सुरक्षा उपकरण

खत्म करो कंपनियों को बनाओ मंडल, भारतीय प्रताड़ना अधिकारी खत्म कर देंगे पूरे विद्युत मंडल की अधोसंरचना

विद्युत मंडल को कंपनियों में बताकर कंपनियों के कार्यों को भी निजीकरण मैं देने के बाद एक तरफ युवा ठेका कर्मियों का भारी तरीके शोषण किया जाता है। बिना प्रशिक्षण व सुरक्षा उपकरण के खम्मा पर चढ़ा दिया जाता है। पिछले 15 सालों से लगातार एक दो युवा ठेका विद्युत कर्मी पूरे देश में हर दिन लापरवाही के शिकार होकर अपंग होने के साथ अकाल मृत्यु का भी शिकार हो जाते हैं। जानने व पढ़ने के बाद बहुत अधिक दुख होता है। अधिकांश ठेका कर्मी युवा हिंदू और अपने माता पिता के अकेले परिवार का एकमात्र सहारा होते हैं। इन सब के दुर्दशाओं के लिए पूर्णतः कंपनियों को शीर्ष पर बैठे महा धूर्त मोटी चमड़ी के महा मक्कार शूकर भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी होते हैं। वह हरामखोर डकैत कंपनियों में आकर केवल लूट और कमाई की व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। उन हरामखोरों को ऐसी लापरवाहियों में होने वाली युवाओं की मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि संबंधित इंजीनियर अधिकारी अगरदुर्घटना की पुष्टि का प्रमाण पत्र दे देतो कम से कम उसके माता-पिता कोचार लाख रुपये दुर्घटना में मृत्यु के मिल सकते हैंपर यह हरामखोर जो नियमित इंजीनियर जिसमें उपयन्त्री सहायक, कार्यपालन यंत्री अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता चूंकि दुर्घटनाओं को रोकने की और कारणों की जांच में वह सब फंसते हैं। इसलिए यह घोर नीच महा भ्रष्ट अपनी या अपने अधीनस्थ इंजीनियरों की लापरवाही स्वीकार ही नहीं करते।

इसलिए उस गरीब युवा टिक करने माता-पिता कोसरकार से मिलने वाली चार लाख रुपए की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त नहीं हो पाती जबकि होना यह चाहिए की कोई भी नियमित ठेका या दैनिक वेतन भोगी किसी की भी मृत्युविभाग में काम करते हुए हो। उन सब का 10 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए तभी किसी कर्मचारी को विद्युत मंडल परिसर में कर्मी के रूप में प्रवेश देना चाहिए। और इसकी व्यवस्था बहुत ज्यादा खर्चीली नहीं है हर ठेकेदार से जो ठेका कर्मी जो विद्युत मंडल की कंपनियों में काम करने के लिए नौकरी पर रखा जा रहा है उन सब के ठहराव पत्र मेंयह एक निश्चित सच जोड़नी चाहिए किवह सभी कर्मियों का सामूहिक बीमा करवा कर ही कंपनी में काम करने के लिए कर्मचारियों को भेजेगा। अन्यथा न केवल पश्चिम परिक्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश व देश की सभी विद्युत के साथ सभी निजी व शासकीय कंपनियों मैं किसी भी कर्मचारी को ठेका कर्मी के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता। और नियुक्त करता है तो किसी भी दुर्घटना में स्वयं ठेकेदार को10 लख रुपए की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

दूसरी तरफ मेरी औद्योगिक स्वास्थ्य एवं संगठन के अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा हुई और मैंने देखा की मात्र भारतीय कारखाना अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत गर्मियों की परिभाषा में जहां उत्पादन कार्य लिखा है वहां उत्पादन एवं सेवा कार्य में लगे सभी कर्मियों को उस कानून के अंतर्गत लाया जाना चाहिए ताकि विद्युत मंडल, संचार, रेल्वे व अन्य सेवा प्रदाता की सारी कंपनियां भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने से वह बहुत सारी सुविधाओं जिसमें कर्मचारी वह उसके परिवार के लोगों का राज्य बीमा निगम में मुफ्त इलाज छुट्टियों के दिनों का भुगतान नियमित छुट्टियां आदि के लाभार्थी हो जाएंगे।

बेशक मैं अपने समाचार पत्र से वह अन्य माध्यम से न केवल सरकार तक बल्कि पूरे विश्व में पहुंचा कर इसके लिए सरकार को कानून परिवर्तन करनेके लिए विवश करने और युवा कर्मियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करूंगा यह मेरा वादा है। और आप मेरे पिछले 25 वर्षों से सतत कर्मचारियों मजदूरों पद मार्गो ठेले पर माल बेचने वालों के हित में समर्पित होकर कार्य करने की शैली को जानते हैं। फिर भी निवेदन है की ठेका कर्मियों दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मियो के सांडों के साथ इंजीनियर संगठन को भी यह मामला ना के ऊपर क्षेत्र विद्युत मंडल कंपनी वरुण पूरे प्रदेश और देश में भी उठाया जाना चाहिए किसी की निर्धनता मजबूरी का यह अर्थ कदापि नहीं कि वह अपने जीवन की कोई कीमत नहीं रखता। हर किसी के जीवन की कीमत होती है और हमें उसको सुरक्षित रखने बचाने के हर संभव प्रयास करने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं।फिर भी आप मुझे अपनी परेशानियां और ऐसी दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी अवश्य भेजते रहें मैं अपने स्तर पर जहां जैसा प्रभु कृपा से सहयोग बनेगा मैं करूंगा ही।

साप्ताहिक समय माया

क्या बीजेपी आरएसएस का एजेंडा पूरा कर रही

शिक्षा में प्रवेश से परीक्षा तक लूट डकैती का तांडव

सरकारी संस्थान बंद किये जा रहे निजी में चारों तरफ हर प्रकार के षड्यंत्र

1930 में स्थापित आरएसएस के एजेंडे में स्पष्ट है कि 95% लोगों को हर तरीके से जाहिल गंवार नंगा भूखा और भिखारी बनाकर रखो। जिसे जर्मनी में एंडोल्फ हिटलर ने अपनाया था। इस एजेंडे पर 1930 में स्थापित आरएसएस ने काम किया था और पिछले 10 सालों मेंजब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है अप्रत्यक्ष रूप से इसी धूर्तता पूर्ण नीति पर पर काम कर रही है।

जब मोदी ने देश में सत्ता संभाली थी। तब 20 करोड लोग गरीबी रेखा के नीचे हुआ करते थे। और 10 साल में मोदी की बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पेट भर उनसे मोटा कमीशन ले उनके लाभ के लिए बनाई नीतियों सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी तालाबंदी ने 5 करोड़ से ज्यादा उद्योग धंधों को बर्बाद कर अब तक 40 करोड़ को बेरोजगार बना 100 करोड़ गरीब बना दिए। जो सरकार के रु. 1 किलो के गेहूं और रु. 2 किलो के चावल पर निर्भर हो जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। फिर भी गरीब गरीबी रेखा से ऊपर निम्न मध्यमवर्गीय एवं मध्यम वर्गीय अपनी किसी प्रकार से बच्चों का शिक्षण करवाना चाहता है जिसे हर तरीके से रोकने का हर शासकीय व निजी शिक्षण संस्थानों मैं षड्यंत्र चलाया जा रहा है अब प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में हर कदम 12 से 15 प्रकार के जाति मूल निवासी आय प्रमाण पत्र आधार कार्ड समग्र आईडी आदि के ढेर सारे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ही एक गरीब को हजार रु. 2000 खर्च करने पड़ रहे हैं और ना बनवाने की हालत में वह बेचारा अपने बच्चों का शिक्षण संस्थान में प्रवेश ही नहीं करवा सकता। आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग जो शासन की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं इन प्रमाण पत्र को बनवाने में उसको अपने इतिहास के 50 वर्षों से ज्यादा समय पूर्व के अपने दादा-दादी, माता-पिता, किस जाति प्रमाण पत्र चाहिए गांव का निवासी बनवाने के लिए भी भी उसको जमीन के कागजात मजदूरी खसरा नंबर आदि प्रमाणित भी चाहिए अन्यथा उसकी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। इसमें कोई शक नहीं इन सब जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आज लगभग सरकारी कार्यालयों में 30 से 70% फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करके सारी सुख सुविधाओं का आनंद भोग कर रहे हैं। परपर इस वर्ष की शिक्षा नीति में इन प्रमाण पत्रों को बनवाने में जितनी दुरूह शर्तों को जोड़ा गया है। और उसको बनवाने में जितनी कैट हैं शब्दावली का प्रयोग किया गया है उससे तो अब निर्धन वर्ग वह विशेष जाति का कोई भी माता-पिता अपने बच्चों केउन सड़कों को पूरा करते हुए जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र बनवा ही नहीं सकेगा और स्वाभाविक है (शेष पेज 6 पर)

भास्कर बैंकिंग • यूजी कोर्स की पहली सूची के साथ फरमान

शासन का नया आदेश- एडमिशन के लिए सालभर की फीस भरना जरूरी

दिनेश जोशी | इंदौर

कॉलेजों में यूजी कोर्स में ऑनलाइन एडमिशन की शनिवार को पहली सूची के साथ ही फीस को लेकर अचानक शासन ने नया फरमान जारी कर दिया। इसके कारण लाखों छात्र सकते में आ गए हैं। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग ने लिस्ट में आने के बाद संबंधित कॉलेज में 1 हजार रुपए जमा कर एडमिशन लेने की व्यवस्था खत्म करते हुए पूरी फीस एक साथ जमा करने का आदेश जारी किया है। छात्रों और अभिभावकों में इसे लेकर खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह अव्यावहारिक है। छात्रों का कहना है कि कई कॉलेजों में बीए एलएलबी की फीस 80 हजार रुपए तक सालाना है। यही नहीं इंदौर के 50 से ज्यादा कॉलेजों ने हाल ही में बीबीए की फीस बढ़ाई गई है। यहां बीबीए की औसत फीस ही 42 हजार तक पहुंच गई है। अब छात्रों को महज आठ दिन की समय-सीमा में पूरी फीस भरना होगी। खुद कॉलेज भी इस निर्णय को अव्यावहारिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे छात्र एडमिशन ही नहीं लेंगे और उनकी सीटें खाली रह जाएंगी।

शिक्षाविदों ने कहा- 80% छात्र आर्थिक तौर पर इतने सक्षम नहीं कि एक साथ राशि भर सकें, निर्णय बदलना चाहिए

इस निर्णय पर शिक्षाविदों ने भी आश्चर्य जताया है। प्राचार्य मंच के अध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार झालानी का कहना है कि इंदौर में प्रवेश लेने वाले 80 फीसदी छात्र या तो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में वे एक साथ 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक फीस कैसे जमा कर सकेंगे। शिक्षाविद् डॉ. रमेश मंगल का कहना है कि यह निर्णय चौंकाने वाला है। इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। हजारों छात्रों के एडमिशन पर ही संकट आ जाएगा।

8.09 लाख कुल सीटें प्रदेश में
1.48 लाख कुल रजिस्ट्रेशन पहले राउंड में
559 कुल शासकीय कॉलेज प्रदेश में।
67 कुल अनुदान प्राप्त कॉलेज प्रदेश में।
682 कुल निजी कॉलेज प्रदेश में।

शासन का तर्क- कोविड के समय दी थी सुविधा- अब पहले जैसा सिस्टम लागू किया

इस मामले में शासन का तर्क है कि एक साथ पूरी फीस भरने की व्यवस्था पहले भी लागू थी। 2012 से 2019 तक यही व्यवस्था थी। लेकिन 2020 में कोविड के दौरान सिर्फ एक हजार रुपए फीस देने की व्यवस्था लागू की थी, ताकि छात्रों व अभिभावकों पर बोझ न आए। उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी धीरेंद्र शुक्ला कहना है कि इस साल से दोबारा पुरानी व्यवस्था ही लागू कर रहे हैं।

3 जून तक भरना है फीस | 25 मई को ही पहली लिस्ट आई है। अब 3 जून तक संबंधित कॉलेजों में फीस जमा करना होगी। जबकि 27 मई से 13 जून तक दूसरे राउंड के रजिस्ट्रेशन होंगे और 19 जून को लिस्ट आएगी।

खंडवा रोड पर जैसे जैसे होगी बसाहट, बढ़ेगी गर्मी

इंदौर में पिछले एक सप्ताह से जिससे बात करो वो गर्मी से परेशान है। कभी शब-ए-मालवा का सेंटर पाइंट था इंदौर, लेकिन अब यहां सडक़ पर निकलने में ऐसा लगता है कि आग में कुद गए हैं। रात को 9 बजे भी सडक़ पर निकलो तो गर्म हवाएं शरीर से ऐसे चिपकती है जैसे दिन के समय निकल रहे हो। इंदौर का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच रहा है, और अभी ये ओर बढ़ेगा। बढ़े भी क्यों नहीं क्योंकि इंदौरी और इंदौर के कथित माई-बाप अंधे जो हो रहे हैं। 1918 में इंदौर का पहला मास्टर प्लान बना था, उसमें इंदौर की सड़कें ही नहीं तय की थी, इंदौर की आबोहवा कैसे बनी रहेगी इसका भी ध्यान रखा गया था। 100 साल पहले इंदौर की भौगोलिक स्थिति को समझा गया था। इस मास्टर प्लान में ही लिखा है कि मालवा के पठार में उपर की ओर इंदौर बसा है और नीचे निमाड़ है। नर्मदा तट से होती गर्म हवाएं उपर उठने के बाद इंदौर की ओर ही आती हैं। इसलिए इंदौर के खंडवा रोड की ओर के हिस्से में निर्माण को बेहद कम करते हुए इसे जंगल और खेतों से भरा-पूरा रखने के लिए ग्रीन बेल्ट तय किया गया था। यही नहीं इस हिस्से को डेन्सग्रीन करने के लिए नौ लाख पेड लगाकर पूरे क्षेत्र को नौलखा बना दिया गया था। लेकिन आज के बेइमान और पैसों के पीछे भागने वाले तथाकथित समझदारों ने इस पूरे इलाके को कांक्रीट का जंगल बनवा दिया है। यहां के जंगलों को काटा जा रहा है, नई कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। यूनिवर्सिटी से लेकर सिमरोल तक नई कॉलोनियां लगातार बस रही हैं। जमीनों के खिलाडियों के लिए इंदौर का ये हिस्सा सोना बरसा रहा है जिसके कुछ टूकड़े इंदौर के कर्ताधर्ताओं के पास भी आ रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि इंदौर का तापमान निमाड के बराबर पहुंच रहा है। पहले मास्टर प्लान में इंदौर को ठंडा रखने के लिए कान्ह-सरस्वती नदी किनारे बड़े पेड लगवाए गए थे, मुख्य सडक़ों के दोनों और छायादार बड़े वृक्ष लगवए थे। जिनमें से कुछ अभी भी नदी के किनारों पर मौजूद हैं। एनजीटी ने भी नदी किनारे हरियाली करने के लिए कहा था। लेकिन इंदौर के कथित खैरखवाहों ने हरियाली के नाम पर नदी किनारे छोटे-छोटे आर्टिफिशियल पौधे लगा दिए, और सडक़ बनाने के लिए यहां बरसों से खड़े पेडों को काट दिया। ये सब होता रहा और इंदौर वाले उसमें खुशहोकर ताली बजाते रहे। प्रचंड गर्मी से बचने के लिए अब कुछ दिमाग के धनियों ने चौराहों पर छांव के लिए ग्रीन नेट लगवाना शुरू कर दी है, ताकी उनका नाम हो सके। लेकिन ये ज्ञानी सडक़ किनारे पेड लगवाने को तैयार नहीं है। हों भी क्यों आखिर इन्हें गर्मी लगती कहां है क्योंकि ये जिस दफ्तर में बैठते हैं वो एसी से ठंडा रहता है जिस गाड़ी से चलते हैं वो चिल्ड एसी वाली होती है। इंदौर की 90 फीसदी जनता जो बाइक पर निकलती है उनकी तरह इन्हें भी एक सप्ताह सडक़ पर घूमवाओ तो ये सब हर साल पेड लगाने के फोटो खिंचवाने की नौटंकी के बजाए हकीकत में पेड लगाने लगेंगे। पेड काटने से क्या होता है तब इन्हें पता चलेगा, लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बात-बात में जुबानी गुस्सा दिखाने वाले इंदौरी अपने हक की बात करने की गर्मी को चापलुसी की बरफ में दबाकर ठंडे हो चुके हैं। ओर ठंडे पड़ चुके लोगों को तो दुनिया से मतलब नहीं रहता है क्योंकि इस तरह के ठंडों का अंत भी गर्मी से ही होता है...

साप्ताहिक
समय माया
samaymaya.com

करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्रों के विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत

साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व samaymaya.com की वेबसाइट पर समाचार, शिकायतें और विज्ञापन (प्रिंट एवं वीडियो) के लिए संपर्क करें

मप्र के समस्त जिलों में एजेंसी देना है एवं संवाददाता नियुक्त करना है

मो. 9425125569 / 9479535569

ईमेल: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958